

सूचना और प्रसारण मंत्रालय



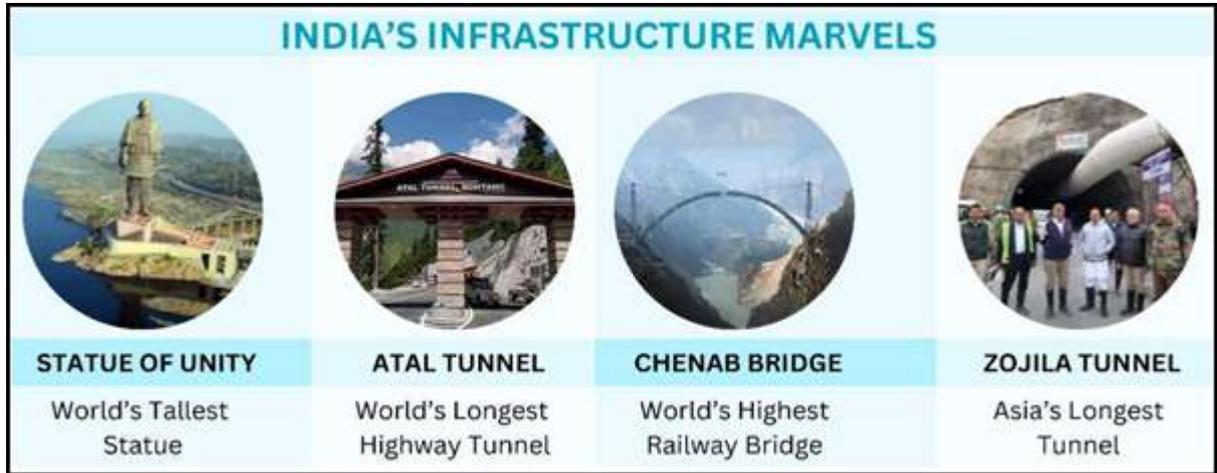
सशक्त भारत का निर्माण

मेक इन इंडिया के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

Posted On: 01 APR 2025 8:13PM by PIB Delhi

परिचय

भारत का बुनियादी ढांचा परिदृश्य विकास और वृद्धि के प्रेरक के रूप में *मेक इन इंडिया* पहल द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। यह समझते हुए कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा आर्थिक प्रगति की रीढ़ है, सरकार ने परिवहन, लोजिस्टिक्स और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू की हैं। भारतमाला परियोजना एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के साथ सड़क संपर्क को बढ़ा रही है, जबकि सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाह आधारित विकास में क्रांति ला रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल एकीकरण के साथ शहरी केंद्रों की फिर से कल्पना कर रहा है और पीएम गति शक्ति माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित कर रहा है। ये पहल अधिक कुशल, परस्पर संबद्ध और टिकाऊ भारत की नींव रख रही हैं।



इस महत्वाकांक्षा का पैमाना उल्लेखनीय उपलब्धियों से मेल खाता है जो भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाएं देश की क्षमताओं के प्रमाण हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग, नवाचार को लचीलेपन के साथ मिश्रित करने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। समर्पित माल ढुलाई गलियारों, आधुनिक हवाई अड्डों और नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिडों का विस्तार एक लचीली और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। बुनियादी ढांचे के विकास को औद्योगिक विस्तार के साथ जोड़कर *मेक इन इंडिया* पहल न केवल भौतिक परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि निवेश, रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी खोल रही है।

अर्थव्यवस्था में तीव्र गति

भारत की आर्थिक वृद्धि रणनीतिक बुनियादी ढांचे की पहलों से प्रेरित है, जिसमें घरेलू विनिर्माण और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए *मेक इन इंडिया* को मुख्य माना गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) विश्व स्तरीय विनिर्माण केंद्र बना रहा है, जबकि पीएम गति शक्ति डेटा-संचालित योजना के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये पहल निर्बाध लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दे रही है, प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे ले जा रही है और भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी)

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी), विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने और पूरे भारत में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को एकीकृत करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाना है, साथ ही आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

CABINET DECISION
28TH AUGUST, 2024

Grand necklace of Industrial Smart Cities

- Cabinet approves 12 Industrial cities under National Industrial Corridor Development Programme
- Estimated investment of Rs. 28,602 crore
- Projects to span across 10 states and strategically planned along 6 major corridors

• Khurpia in Uttarakhand	• Gaya in Bihar
• Rajpura-Patlala in Punjab	• Zaheerabad in Telangana
• Dighi in, Maharashtra	• Orvakal and Kopparthi in AP
• Palakkad in Kerala	• Jodhpur-Pali in Rajasthan
• Agra and Prayagraj in UP	

1/2

प्रमुख गतिविधियां

- अगस्त 2024 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी के तहत 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी।
- छह प्रमुख गलियारों के साथ नियोजित ये औद्योगिक नोड भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देंगे।

पीएम गति शक्ति

2021 में लॉन्च किया गया, पीएम गति शक्ति – मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, विनिर्माण और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करके *मेक इन इंडिया* के विजन को मजबूत करता है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और परियोजना में देरी को कम करने के लिए भू-स्थानिक मानचित्रण और डेटा-संचालित निर्णय लेने को एकीकृत किया जाता है। कनेक्टिविटी को सुव्यवस्थित करके यह

औद्योगिक गलियारों को मजबूत करता है, कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करता है और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करता है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) द्वारा किया जाता है ताकि निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

13 मार्च, 2025 तक **6.38** लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ लगभग **13,500** किलोमीटर को कवर करने वाली **115** राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन इस पहल के तहत किया गया है, जिससे अधिक कुशल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क एवं समुद्री संपर्क

भारत के सड़क और समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करना *मेक इन इंडिया* विजन का मुख्य उद्देश्य है। इससे उद्योगों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतमाला और सागरमाला जैसी रणनीतिक पहल माल ढुलाई को बढ़ा रही हैं, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार कर रही हैं और भारत की विनिर्माण और व्यापार महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही हैं।

भारतमाला परियोजना

भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों, एक्सप्रेसवे और संपर्क सड़कों के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करके भारत के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ा रही है। *मेक इन इंडिया* दृष्टिकोण के अनुरूप यह कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, प्रमुख केन्द्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह पहल न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी बल्कि स्वदेशी विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को भी समर्थन देगी, जिससे भारत अपने परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। 2017 में इसकी स्वीकृति के बाद से इस पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है:

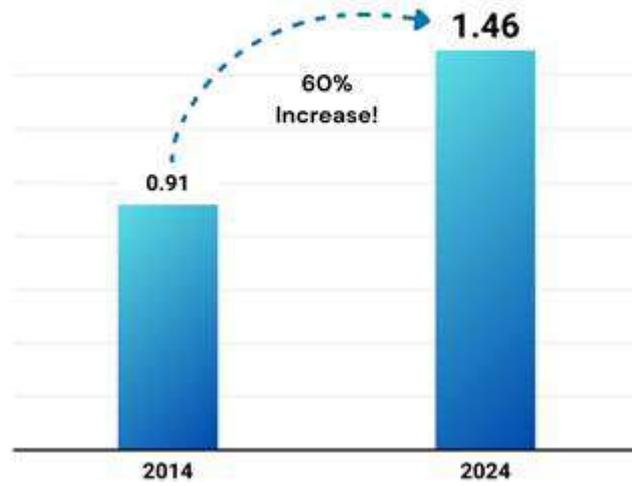
- 28 फरवरी, 2025 तक, **34,800 किलोमीटर** की योजना के तहत **26,425 किलोमीटर** की परियोजनाएं आवंटित की गईं, जिनमें से **19,826 किलोमीटर** का निर्माण पहले ही हो चुका है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कुल व्यय **4,92,562** करोड़ रुपये है।
- फरवरी 2025 तक **6,669 किलोमीटर** हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य स्वीकृत, जिसमें से **4,610 किलोमीटर** का काम पूरा हो चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

पिछले दशक में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो उच्च बजट आवंटन और तेजी से होने वाले निर्माण के कारण संभव हुआ है। नेटवर्क 2014 में **91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1,46,145 किलोमीटर** हो गया है, जो **60 प्रतिशत की वृद्धि** को दर्शाता है। इस विस्तार से कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यात्रा का समय कम हुआ है तथा देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

India's National Highway Network

(In Lakh KM)



सागरमाला

वर्ष 2015 में शुरू किया गया सागरमाला कार्यक्रम देश के व्यापक समुद्र तट और जहाजों के लिए जलमार्गों की क्षमता का दोहन करने के लिए बंदरगाह आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके भारत की विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका ध्यान बंदरगाह अवसंरचना, संपर्क में सुधार और तटीय आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित है, जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, रो-पैक्स फेरी सेवाएं, कूज टर्मिनल और तटीय समुदायों के लिए कौशल विकास जैसी पहल आत्मनिर्भर समुद्री इकोसिस्टम के विकास में योगदान देती हैं, जो वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।



अपनी स्वीकृति के बाद से इस पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- 19 मार्च, 2025 तक सागरमाला के तहत 5.79 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 839 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 1.41 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- समुद्री व्यापार दक्षता को मजबूत करने के लिए बंदरगाह संपर्क और तटीय बुनियादी ढांचे में वृद्धि।

रेल आधारभूत संरचना

भारत के रेल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे संपर्क, सुरक्षा और शहरी मोबिलिटी मजबूत हुई है। वंदे भारत ट्रेनों और मेट्रो रेल विस्तार जैसी प्रमुख पहलों से यात्री अनुभव में सुधार हो रहा है, ट्रांजिट हब का आधुनिकीकरण हो रहा है और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो रही है। *मेक इन इंडिया* विजन के तहत रेलवे नेटवर्क विस्तार को बढ़ावा देना, समावेशी विकास और कुशल परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

वंदे भारत ट्रेनें

2019 में लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनें *मेक इन इंडिया* विजन का उदाहरण हैं, जो रेलवे आधुनिकीकरण में देश की इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के रूप में इनमें आधुनिक कोच, उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ और बेहतर यात्री सुविधाएँ शामिल हैं। स्वचालित प्लग दरवाज़ों, एर्गोनॉमिक रिक्लाइनिंग सीटों और व्यक्तिगत मोबाइल चार्जिंग सॉकेट से सुसज्जित ये ट्रेनें एक बेहतरीन यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं। मध्यम और छोटी दूरी के मार्गों पर परिचालन करते हुए, वे कनेक्टिविटी में सुधार करते हैं तथा यात्रा के समय को काफी कम कर देते हैं।

भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के साथ लंबी दूरी की यात्रा को भी बदलने की तैयारी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा निर्मित पहले 16-कार सेट ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर 540 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सफल परीक्षण पूरे किए। 17 दिसंबर 2024 को इसका निर्माण पूरा होने के बाद कोटा डिवीजन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर ट्रेन का परीक्षण किया गया, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए आराम और हाई परफॉर्मेंस सुनिश्चित हुआ।

अपनी शुरूआत के बाद से इस पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- 18 मार्च, 2025 तक पूरे भारत में **136** वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करती हैं।
- विविध परिचालन कार्यक्रमों में सप्ताह में छह दिन चलने वाली 122 सेवाएं, सप्ताह में चार दिन चलने वाली 2 सेवाएं, 8 त्रि-साप्ताहिक और 4 साप्ताहिक सेवाएं शामिल हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना

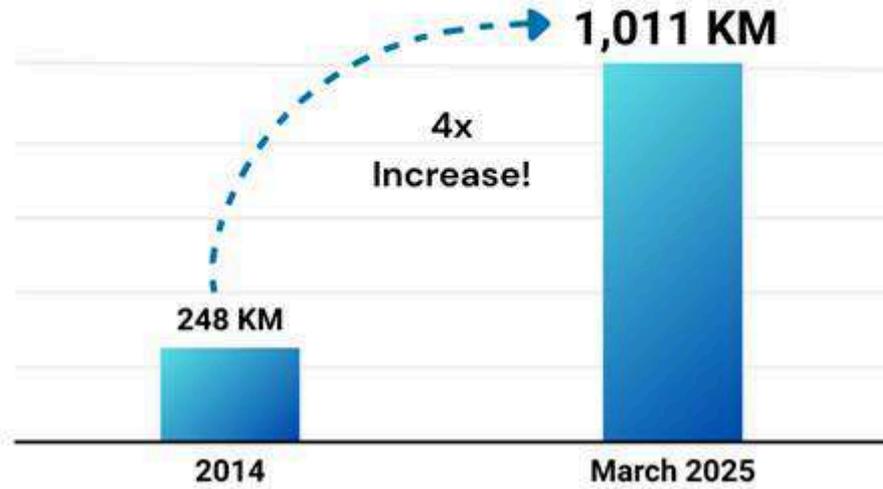
अमृत भारत स्टेशन योजना भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक दीर्घकालिक पहल है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और समग्र बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक ट्रांजिट हब्स में बदलना है। 12 मार्च, 2025 तक **1,337 स्टेशनों** को अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया गया है, ताकि बेहतर पहुंच, बेहतर सुविधाएं और निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

मेट्रो रेल विस्तार

भारत की मेट्रो रेल प्रणाली शहरी परिवहन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो पारंपरिक आवागमन विधियों के लिए एक तेज, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। प्रमुख शहरों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर सरकार के बढ़ते ध्यान के साथ नेटवर्क के विस्तार में तेजी आई है। 2014 के बाद से, मेट्रो प्रणाली तेजी से विकसित हुई है, जिससे भीड़भाड़ कम हुई है और शहरी मोबिलिटी बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली 'शेड्यूल ए' कंपनी बीईएमएल लिमिटेड ने मेट्रो कोच निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। मई 2024 तक, बीईएमएल ने दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बैंगलोर और मुंबई सहित विभिन्न मेट्रो निगमों को 2,000 से अधिक मेट्रो कोच की आपूर्ति की है।

मेट्रो नेटवर्क के अलावा भारत ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की शुरूआत के साथ भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनें, विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र और अधिक कुशल यात्रा उपलब्ध कराते हुए जन परिवहन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख उदाहरण हैं।

Expansion of India's Metro Rail Network



अपनी शुरूआत के बाद से इस पहल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है:

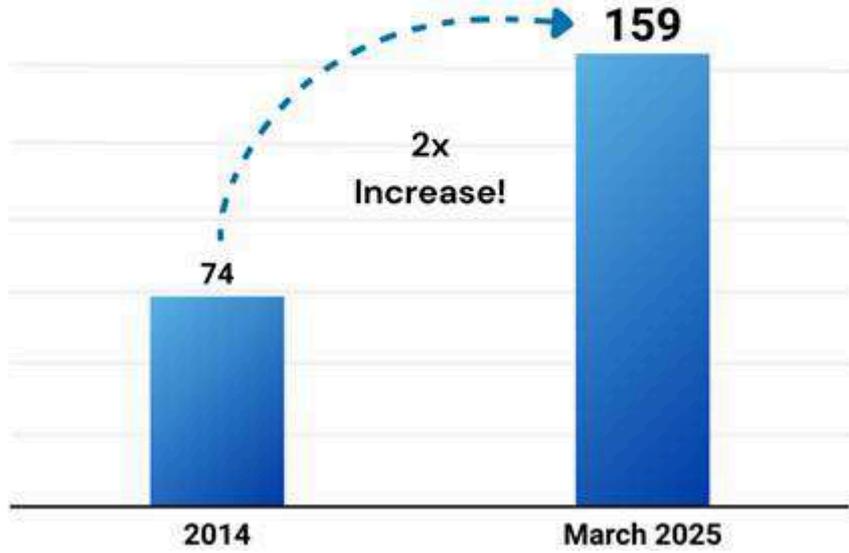
- मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किमी से बढ़कर मार्च 2025 तक **1,011 किलोमीटर** हो गया है, जो 20 से अधिक शहरों को कवर करता है।
- दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली नमो भारत ट्रेन अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाती है।

नागर विमानन

भारत के विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो बढ़ती मांग और हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से सक्रिय सरकारी नीतियों से प्रेरित है। इस तीव्र विस्तार ने भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना दिया है। क्षेत्रीय संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के फोकस ने देश भर में बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है, जिससे आर्थिक विकास और मोबिलिटी को बढ़ावा मिला है।



Number of Operational Airports in India



विस्तार के लिए अपने प्रयासों के बाद से इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं:

- परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर मार्च 2025 तक **159** हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा।
- 17 नवंबर, 2024 को घरेलू हवाई यात्री यातायात एक दिन में **5 लाख** को पार कर गया, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया।
- उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की संख्या जून 2016 में 29 से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 38 हो गई, जिसके तहत **57 बेस** हो जाएंगे, इससे पायलट प्रशिक्षण क्षमता मजबूत होगी।

निष्कर्ष

भारत के बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसने औद्योगिक विकास और आर्थिक विस्तार के लिए आधार तैयार किया है। सड़क, रेल, समुद्री, विमानन और शहरी विकास में ऐतिहासिक परियोजनाओं ने न केवल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाई है। राष्ट्रीय राजमार्गों, मेट्रो नेटवर्क और आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ पीएम गति शक्ति और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी परिवर्तनकारी योजनाएं निरंतर विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार में निरंतर निवेश के साथ, भारत उद्योगों के लिए नए अवसर खोलने, रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी।

संदर्भ:

- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/mar/doc2024314323901.pdf>
- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/mar/doc2025327528301.pdf>
- <https://www.investindia.gov.in/faq-pdf/87/en>
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2385_aHLSRV.pdf?source=pqals
- <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098788>
- <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098788>
- <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2100409®=3&lang=1>
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3059_z2v6Ah.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4460_65YXUj.pdf?source=pqals

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AS189_1gSlts.pdf?source=pqals
- <https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151908&ModuleId=3®=3&lang=1>
- <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2050136>
- <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003463>
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2484_IDSz1v.pdf?source=pqals
- <https://www.bemlindia.in/rail-and-metro/>
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3730_g379BT.pdf?source=pqals

कृपया पीडीएफ फाइल देखने के लिए यहां क्लिक करें

एमजी/आरपीएम/केसी/डीवी

(Release ID: 2117745)

Read this release in: English , Urdu , Gujarati , Telugu